शामिल है, सदन के पटल पर रखे गए विवरण में दिए गए हैं (नीचे देखिए)।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

वर्ष के दौरान वित्त और विविध आय सहित प्रचालन आय

	पत्तन न्यास का नाम	1992-93	1993-94	1994-95 (करोड़ रु०)
1.	बम्बई पत्तन न्यास	437.22	484.82	558.51
2.	कलकत्ता पत्तन न्यास	335.46	413.20	468.62
3.	कोचीन पत्तन न्यास	80.56	80.69	94.61*
4.	जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास	103.50	124.28	179.07
5.	कांडला पत्तन न्यास	119.48	139.96	157.97
6.	मद्रास पत्तन न्यास	256.64	300.29	310.08
7.	मुरगांव पत्तन न्यास	79.12	98.96	97.41
8.	न्यू मंगलोर पत्तन न्यास	41.97	48.31	48.21
9.	पारादीप पत्तन न्यास	103.03	132.73	138.37*
10.	तूतीकोरिन पत्तन न्यास	39.88	39.09	45.02
11.	विशाखापत्तनम पत्तन न्यास	189.56	202.26	219.41
		1786.42	2064.59	2317.28

*आंकड़े अनन्तिम हैं।

गुजरात द्वारा कच्छ क्षेत्र के लिये पृथक विकास बोर्ड बनाने की मांग

946. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कच्छ क्षेत्र के लिए एक पृथक विकास बोर्ड बनाने और इस प्रयोजनार्थ संविधान के अनुच्छेद 371 में संशोधन करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस लंबित मांग को स्वीकृति प्रदान करने हेतु सरकार से अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने अब तक इस पर क्या कार्रवाई की है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० कामसन): (क) से (ङ) गुजरात सरकार ने महाराष्ट्र के विकास बोर्डों की भांति ही "कच्छ विकास बोर्ड" की स्थापना के लिए अनुमोदन चाहा है। हालांकि, राज्य सरकार से इस अनुरोध पर कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए हैं, फिर भी यह महसूस किया जाता है कि मामले की विभिन्न कानूनी, संवैधानिक एवं राजनैतिक जटिलताओं को देखते हुए, इस मामले में निर्णय लिए जाने के लिए कोई निश्चित समय सीमा बताना संभव नहीं है।

Food processing units in economically and industrially backward areas of Madhya Pradesh

947. SHRI DILIP SINGH JUDEV: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether Government have received any proposal for setting up food processing units in economically and industrially backward areas of the State

of Madhya Pradesh in 1994-95, 1995-96;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the details of Food Processing Units set up in the backward regions of the Madhya Pradesh during the last three years?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI K.P. SINGH DEO): (a) and (b) As per available information during April, 1994 to October, 1995, 52 Industrial Entrepreneurs Memoranda (IEMs) envisaging an investment of Rs. 439 crores approximately and direct employment of 6177 persons have been filed for the backward areas of Madhya Pradesh for setting up of units in the various sectors of Food Processing.

(c) Since August, 1991 and till October, 1995, 48 Food Processing Units have been set up in the backward areas of Madhya Pradesh involving an investment of Rs. 341 crores.

"मोटी खावड़ी" पेट्रोरसायन परियोजना की समीक्षा किया जाना

948. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार एक गैर-सरकारी कम्पनी को सौंपी गई "मोटी खावड़ी" पेट्रो-रसायन परियोजना की समीक्षा करने का विचार रखती है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या-क्या मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं और राज्य सरकार की इन पर क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा): (क) रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को गुजरात के जामनगर जिले के मोटी खावड़ी गांव में नाफ्था क्रैकर, एम ई जी, पैराक्सीलीन और एल डी पी ई परियोजनाएं स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा आशय-पत्र स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा इस कंपनी ने किसी स्थान पर कई अन्य डाऊनस्ट्रीम परियोजनाएं कार्यान्वित करने के लिए सरकार के पास उधमी सूचना ज्ञापन दर्ज कराया है। सरकार द्वारा इनमें से किसी भी परियोजना का पुनरीक्षण किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Classification of Uttarakhand Region as Economically Backward Area

949. SHRI CHATURANAN MISHRA:
SHRI GAYA SINGH:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are considering a proposal to classify the entire Uttarakhand region as an economically backward area;

(b) if so, the details thereof; and

(c) what is Government's reaction to the demand for a separate State of Uttarakhand?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFAIRS (PROF. M. KAMSON): (a) and (b) The matter is under consideration of the Government in the light of relevant pronouncements of the Supereme Court.

(c) The Government of India do not propose to reorganise the present set up of States.

Increase of Staff Strength in Indian Missions Abroad

950. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in our Missions abroad the work of Consular Sections which processes the applications for grant/renewal of passports and issue of visas has increased and there has not been any commensurate increase in the staff strength; and

(b) if so, what steps have been taken to increase staff strength in those Missions?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI R.L. BHATIA): (a) and (b) The number of consular posts sanctioned in Missions abroad is based on laid down norms regarding time taken for each consular service. Accordingly, increase in